न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

बनाम

गोपाली एवं अन्य

सिविल अपील सं. 5179/2012

5 जुलाई 2012

(जीएस सिंघवी और सुधांशु ज्योति मुखोपाध्याय, जे.जे.)

मोटर वाहन अधिनियम, 1988: धारा 166 - मोटर दुर्घटना-पीड़ित की मृत्यु-मुआवजे का दावा-मृतक की आय की गणना- आय में वृद्धि पर विचार- अभिनिर्धारित: उच्च न्यायालय मुआवजे की राशि निर्धारित करने में मृतक की आय में 100% वृद्धि प्रदान करने में न्यायसंगत था - सामान्य तौर पर, मृतक ने 22 साल तक सेवा करता और उस अवधि के दौरान उसका वेतन निश्चित रूप से दोगुना हो गया होता क्योंकि नियोक्ता प्रति वर्ष उसके वेतन का 20 प्रतिशत बोनस के रूप में भुगतान कर रहा था - आक्षेपित आदेश के लिए बीमाकर्ता की चुनौती गुणहीन है।

मोटर दुर्घटना-पीड़ित की मृत्यु- मुआवजा- व्यक्तिगत खर्चों के लिए कटौती- अभिनिर्धारित: उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने मृतक के व्यक्तिगत खर्चों के लिए 1/3 की कटौती के नियम का अनुसरण नहीं करके कोई त्रुटि नहीं की- वर्तमान मामले में, मृतक के पास चार बेटे और एक बेटी सहित 8 आश्रित थे - जहां मृतक के परिवार में 5 या उससे अधिक व्यक्ति शामिल हैं जिनकी आय 3,000/- रुपये से 5,000/- रुपये की है, यह वस्तुतः उसके लिए असंभव है कि वह कुल आय के 1/10 हिस्से को स्वयं पर खर्च करे।

मोटर दुर्घटना-क्षतिपूर्ति-गुणक- मृतक की आयु लगभग 36 वर्ष-अभिनिर्धारितः न्यायाधिकरण और उच्च न्यायालय 10 के गुणक को लागू करने में सही नहीं थे - यह एक उपयुक्त मामला है जिसमें न्यायालय को संविधान की धारा 142 के तहत शक्ति का प्रयोग करना चाहिए और उचित गुणक लागू करके उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित मुआवजे को बढ़ाना चाहिए। दावेदारों के साथ पूर्ण न्याय करने के लिए, 15 के गुणक को लागू करके मुआवजे की राशि को पुनः निर्धारित किया गया और तदनुसार, दावेदार कुल 10,63,040/- की राशि के हकदार हैं जैसा कि निर्णय में विस्तृत रूप से दिया गया है- दावा याचिका दायर करने की तारीख से दावेदारों को बढ़े हुए मुआवजे पर 12 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज मिलेगा -ब्याज- भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 142।

लागतः मुआवजे के भुगतान में देरी- न्यायाधिकरण द्वारा दिया गया मुआवजा उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा बढ़ाया गया, उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा पुष्टि - अभिनिर्धारितः चूंकि बीमाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित पूर्व-पक्षीय अंतरिम आदेश का पांच साल की अवधि के लिए लाभ लिया था, उसको निर्देश दिया जाता है कि वह 5 लाख रुपये की लागत का भुगतान दावेदारों को करे।

न्याय प्रशासनः न्यायाधिकरण द्वारा प्रदत्त मुआवजे को चुनौती देने वाली बीमाकर्ता की अपील, उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा बढ़ाया गया और खंड-पीठ द्वारा पुष्टि की गई। उच्च न्यायालय की पीठ- एकपक्षीय अंतरिम आदेश-न्यायालय ने इस संबंध में अपनी चिंता व्यक्त की पूर्व-पक्षीय अंतरिम आदेश कई वर्षों तक जारी रहा, मामले को प्रभावी सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किए बिना- अंतरिम आदेश - एकतरफा अंतरिम आदेश- प्रथा और प्रक्रिया।

संतोष देवी बनाम राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड और अन्य 2012(3) एससीआर 1178 पर- भरोसा किया गया।

महाप्रबंधक, केरल राज्य सड़क परिवहन निगम बनाम सुसम्मा थॉमस (1994) 2 एस.सी.सी. 176; सरला वर्मा बनाम दिल्ली परिवहन निगम 2009 (5) एससीआर 1098 = (2009) 6 एस.सी.सी. 121; *यू.पी.एसआरटीसी बनाम* त्रिलोक चंद्र (1996) 4 एस.सी.सी. 362 और फकीरप्पा बनाम कर्नाटक सीमेंट पाइप कारखाना 2004 (2) एस.सी.आर. 369 = (2004) 2 एस. सी.सी. 473-संदर्भित ।

मामला कानून संदर्भः

(1994) 2 एससीसी 176 -	संदर्भित किया गया-	पैरा 7
2009 (5) एससीआर 1098-	संदर्भित किया गया -	पैरा 14
(1996) 4 एस.सी.सी. 362 -	संदर्भित किया गया है-	पैरा 15
2004 (2) एससीआर 369 -	संदर्भित किया गया है-	पैरा 15
2012 (3) एससीआर 1178-	भरोसा किया गया-	पैरा 16

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील सं 5179/2012

डी.बी. विशेष अपील सं. 49/2005 में जयपुर स्थित राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ के निर्णय और आदेश दिनांकित 22.03.2007 से।

अपीलार्थी के लिए निकुंज दयाल, प्रमोद दयाल।

न्यायालय का आदेश दिया गया-

आदेश

1. अनुमति दी गई।

2. भारत एक समृद्ध संवैधानिक व्यवस्था, एक आविष्कारशील और सक्रिय न्यायपालिका, एक कुशल बार द्वारा सहायता प्राप्त और राज्य द्वारा समर्थित होने के लिए प्रशंसित है। हालाँकि, जिन न्यायालयों और न्यायाधिकरणों से नागरिकों को अपनी शिकायतों के निवारण और अपने मौलिक, संवैधानिक और कानूनी अधिकारों की सुरक्षा के लिए संपर्क करने की उम्मीद की जाती है, वे देरी और लागत की समस्याओं से घिरे हुए हैं। ऐसे देश में जहां 36 प्रतिशत आबादी गरीबी रेखा से नीचे रहती है, न्याय वितरण प्रणाली में ये कमियां आबादी के एक बड़े हिस्से को कानूनी उपायों का लाभ उठाने से रोकती हैं। वंचित और गरीब मुकदमेबाजी की लागत, वास्तविक खर्च और खोए अवसरों दोनों के कारण न्याय तक पहुंच से वंचित हैं, और सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय हासिल करने का प्रशंसनीय लक्ष्य जो भारत के संविधान की प्रस्तावना में निहित है, उनके लिए एक भ्रम है। न्यायालयों का बुनियादी ढाँचा और उन्हें नियंत्रित करने वाली प्रक्रियाएँ गरीबों के लिए बिल्कुल दुर्गम हैं। राज्य, जिसे संविधान के अनुच्छेद 39ए द्वारा यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया है कि कानूनी प्रणाली का संचालन मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करके न्याय को बढ़ावा दे, और आर्थिक या अन्य विकलांगताओं के कारण किसी भी नागरिक को न्याय हासिल करने के अवसरों से वंचित नहीं किया जाये, गरीबों, दलितों और वंचितों को न्याय सुलभ कराने के लिए कोई प्रभावी तंत्र नहीं बना पाया है। पिछले ढाई दशकों में कानूनी सेवा प्राधिकरण की संस्था ने गरीबों को कानूनी सहायता प्रदान करने के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवा प्रदान की है, लेकिन समाज के आर्थिक रूप से वंचित वर्ग और अशिक्षा और अज्ञानता जैसी अन्य विकलांगताओं से पीड़ित लोगों को न्याय सुनिश्चित करने के लिए बहुत कुछ किया जाना बाकी है।

3. हमने राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा पारित आदेश दिनांकित 22.3.2007 के खिलाफ दायर इस याचिका के निपटान की प्रस्तावना दी है, जिसमें अपीलकर्ता द्वारा विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले के खिलाफ दायर की गई है जिसमें विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले के के खिलाफ अपीलर्थी द्वारा दायर विशेष अपील को सुनवाई योग्य नहीं होने के कारण उपर्युक्त टिप्पणियाँ करते हुए खारिज कर दिया गया था, क्योंकि पिछले लगभग 20 वर्षों में दावेदारों - नानग राम के वृद्ध माता-पिता, पत्नी और पांच बच्चे, जो 1992 में सड़क दुर्घटना का शिकार हो गए थे, ने उच्च न्यायालय चरण तक मुकदमा चलाने और मुकदमेबाजी में अपने सभी संसाधनों को समाप्त कर दिया होगा और उनके पास इस न्यायालय में एक वकील नियुक्त करने के लिए पर्याप्त धन नहीं बचा होगा और इसलिए भी कि पिछले लगभग पांच वर्षों में, जिसके दौरान विशेष अनुमति याचिका इस न्यायालय में लंबित रही, उन्होंने न्याय पाने की सभी उम्मीदें खो दी होंगी। उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (संक्षेप में, 'अधिनियम') की धारा 173 के तहत नानग राम के आश्रितों द्वारा दायर अपील की अनुमति दी थी और मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण जयपुर (संक्षेप में, 'न्यायाधिकरण'), द्वारा दिए गए मुआवजे को 4,85,000/- रुपये की राशि से बढ़ा दिया था और अपीलकर्ता को दावा याचिका दायर करने की तारीख से 31.12.2000 तक 12 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ बढ़ा हुआ मुआवजा देने का निर्देश दिया, और 1.1.2001 से उसके भुगतान तक 9 प्रतिशत की दर से, लेकिन 23.7.2007 को इस न्यायालय द्वारा पारित एकपक्षीय अंतरिम आदेश के कारण, दावेदारों को 2 लाख रु की मामूली राशि मिल सकी और उन्होंने शायद सोचा कि अपीलकर्ता द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका के विरुद्ध पर लड़ने के लिए पैसा खर्च करना उचित नहीं होगा। शायद यह हजारों गरीब वादकारियों की सोच है, जो निचली अदालतों और उच्च न्यायालयों में तो सफल हो जाते हैं, लेकिन देश की सर्वोच्च

अदालत में मुकदमा लड़ने की लागत और खर्च वहन नहीं कर पाते हैं और सर्वशक्तिमान ईश्वर के नाम पर, इसे अपनी नियति मान कर चुपचाप पीड़ा सहते हैं।

4. नानग राम की 9.3.1992 को हुई एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई जब उनकी मोटरसाइकिल को प्रतिवादी संख्या 10-राम चंद्र पालीवाल के स्वामित्व वाले और रघु नाथ द्वारा संचालित ट्रक ने टक्कर मार दी थी, जिसका नाम दिनांक 2.4.2009 के आदेश के तहत पार्टियों की सूची से हटा दिया गया था। दुर्घटना के समय नानग राम की उम्र लगभग 36 वर्ष थी और वह नेशनल इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड, जयपुर में 4,000/- रुपये प्रति माह वेतन पर मशीन ऑपरेटर के पद पर कार्यरत थे।

5. नानग राम के आश्रितों ने अधिनियम की धारा 166 के तहत 24 लाख रुपये के मुआवजे के लिए एक याचिका दायर की, जिसमें आरोप लगाया गया कि श्री रघु नाथ द्वारा ट्रक को तेजी से और लापरवाही से चलाने के कारण उनकी रोटी कमाने वाले की मृत्यु हो गई। जबकि ट्रक के मालिक और उसके चालक ने दावा याचिका का विरोध करने के लिए कोई जवाब दाखिल नहीं किया, अपीलकर्ता ने सभी संभावित आपत्तियां उठाईं। अपीलकर्ता की ओर से दायर जवाब में प्रार्थना की गई कि दावेदारों को यह साबित करने का निर्देश दिया जाए कि क्या दोषी वाहन का चालक मालिक के यहाँ नौकरी करता था, और क्या उसके पास वैध और प्रभावी ड्राइविंग लाइसेंस था। अपीलकर्ता ने मूल बीमा पॉलिसी पेश करने के लिए मालिक को निर्देश देने की भी मांग की और, जैसा कि आमतौर पर ऐसे मामलों में किया जाता है, यह दावा किया कि दुर्घटना ट्रक की तेज और लापरवाही से ड्राइविंग के कारण नहीं हुई थी। अपीलकर्ता द्वारा एक वैकल्पिक दलील यह थी कि यदि कोई निर्णय पारित किया जाता है, तो दोनों ड्राइवरों की अंशदायी लापरवाही निर्धारित की जाए।

6. पक्षों की दलीलों और सबूतों पर विचार करने के बाद, न्यायाधिकरण ने माना कि दुर्घटना ट्रक की तेज और लापरवाही से ड्राइविंग के कारण हुई थी। न्यायाधिकरण ने दावेदारों के इस दावे को भी स्वीकार कर लिया कि मृतक नेशनल इंजीनियरिंग कंपनी, जयपुर में मशीन ऑपरेटर के रूप में कार्यरत था। इसके बाद न्यायाधिकरण ने मृतक की मासिक आय के मुद्दे पर दावेदारों द्वारा पेश किए गए सबूतों का हवाला दिया और कहा कि इसे 3,000/- रुपये प्रति माह के रूप में लिया जा सकता है। व्यक्तिगत खर्चों के लिए एक तिहाई की कटौती करने और 10 के गुणक को लागू करने के बाद, ट्रिब्यूनल ने निष्कर्ष निकाला कि दावेदार 5.9.1992 से 12 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ 2,55,000/- रुपये के कुल मुआवजे के हकदार हैं।

7. उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने इस तथ्य का संज्ञान लेते हुए कि नियोक्ता मृतक को सालाना उसके वेतन के 20 प्रतिशत की दर से बोनस का भुगतान कर रहा था, महाप्रबंधक, केरल राज्य सड़क परिवहन निगम बनाम सुसम्मा थॉमस (1994) 2 एससीसी 176 में इस न्यायालय के फैसले का हवाला दिया, और माना गया कि दावेदार कुल 6,45,300/- रुपये के मुआवजे के हकदार हैं। विद्वान एकल न्यायाधीश ने दर्द और पीड़ा, प्यार और स्नेह की हानि, सह-व्यवस्था, सुरक्षा और संरक्षण के लिए छोटी रक़मों को जोड़ दिया और अपीलकर्ता को 12 प्रति की दर से ब्याज के साथ 4,85,000/- रुपये की अतिरिक्त राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया। प्रतिवर्ष प्रतिशत.

8. अपीलकर्ता द्वारा दायर विशेष अपील को उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच ने सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 100 ए पर भरोसा करते हुए खारिज कर दिया था।

9. 23.7.2007 को, इस न्यायालय ने विशेष अनुमति याचिका पर नोटिस का आदेश दिया और अप्रत्यक्ष रूप से उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले पर रोक लगा दी। संदर्भ के लिए वह आदेश नीचे दिया गया है:

"नोटिस जारी करें।

शामिल दावों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, याचिकाकर्ता को आज से चार सप्ताह के भीतर संबंधित एमएसीटी के पास तीन लाख रुपये की राशि जमा करने दें। दावेदार को सिक्योरिटी प्रस्तुत किए बिना दो लाख रुपये की राशि निकालने की अनुमति दी जाएगी।

10. जैसा कि बड़ी संख्या में अन्य विशेष अनुमति याचिकाओं का हश्र होता है, इस याचिका को प्रभावी सुनवाई के लिए अगले पांच वर्षों तक न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध नहीं किया गया और अपीलकर्ता एकपक्षीय अंतरिम आदेश का लाभ उठाता रहा। पहली बार मामला 15.10.2008 को यानी नोटिस जारी होने के लगभग एक साल और तीन महीने बाद रजिस्ट्रार के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था। रजिस्ट्रार ने नोट किया कि प्रतिवादी संख्या 1 से 8 और 10 को नोटिस नहीं दिया गया है और पार्टियों की श्रृंखला से प्रतिवादी संख्या 9 को हटाने के लिए एक आवेदन दायर किया गया है। 2.4.2009 को चैंबर न्यायाधीश द्वारा आवेदन की अनुमति दे दी गई। अगले दो साल और पांच महीने तक मामले की फाइल सामने नहीं आई। 14.9.2011 को, मामला रजिस्ट्रार के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था, जिन्होंने अपीलकर्ता के वकील का बयान दर्ज किया था कि वह प्रतिवादी नंबर 1 और 3 के कानूनी प्रतिनिधियों को रिकॉर्ड पर नहीं लाना चाहते हैं। 12.10.2011 को मामला फिर से रजिस्ट्रार के समक्ष सूचीबद्ध किया गया, जिन्होंने निर्देश दिया कि मामला चैंबर न्यायाधीश के समक्ष रखा जाए। जब मामला चैंबर न्यायाधीश के समक्ष सूचीबद्ध किया गया, तो उन्होंने कहा कि प्रतिवादी

नंबर 1 और 3 के कानूनी प्रतिनिधि पहले से ही अभिलेख में हैं। यह उन लोगों के लिए चिंता का विषय होना चाहिए जो इस संस्था से जुड़े हैं कि न्यायालय द्वारा पारित एकपक्षीय अंतरिम आदेश मामले को प्रभावी सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किए बिना वर्षों तक क्यों जारी रहना चाहिए। यदि दावेदार समाज के आर्थिक रूप से संपन्न वर्ग के सदस्य होते, तो उन्होंने एक प्रतिष्ठित वकील को नियुक्त किया होता और मामले की शीघ्र सुनवाई के लिए कदम उठाए होते, लेकिन, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, उनके पास विशेष अनुमति याचिका लड़ने के लिए कोई वकील करने की वित्तीय क्षमता और संसाधन नहीं हैं।

11. हमने अपीलकर्ता के विद्वान वकील को सुना है और रिकॉर्ड का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया है।

12. हमारे विचार में, आक्षेपित आदेश के प्रति अपीलकर्ता की चुनौती निराधार है और अपील खारिज किये जाने योग्य है। हम यह भी मानते हैं कि यह एक उपयुक्त मामला है जिसमें न्यायालय को संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत शक्ति का प्रयोग करना चाहिए और उचित गुणक लागू करके उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित मुआवजे को बढ़ाना चाहिए।

13. हम पहले इस बात पर विचार करेंगे कि क्या उच्च न्यायालय द्वारा मृतक के व्यक्तिगत खर्चों के लिए एक तिहाई कटौती के नियम को लागू नहीं करना उचित था।

14. सरला वर्मा बनाम दिल्ली परिवहन निगम (2009) 6 एससीसी 121 में, दो न्यायाधीशों की पीठ ने बीमाकर्ता और/या दोषी वाहन के मालिक द्वारा देय मुआवजे के निर्धारण के लिए मापदंडों को मानकीकृत करने का प्रयास किया। व्यक्तिगत खर्चों के लिए कटौती के मुद्दे से निपटते समय, न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणियाँ कीं:

"हमने पहले ही देखा है कि आश्रितों को हिस्सा देने के लिए मृतक के व्यक्तिगत और जीवन-यापन के खर्च को आय से घटाया जाना चाहिए। मृतक के वास्तविक खर्चों को दिखाने के लिए किसी सबूत की आवश्यकता नहीं है। वास्तव में, इस संबंध में कोई भी साक्ष्य पूरी तरह से संदिग्ध होगा और उसके अविश्वसनीय होने की संभावना है। दावेदार स्पष्ट रूप से यह दावा करेंगे कि मृतक बहुत मितव्ययी था और उसकी कोई खर्चीली आदत नहीं थी और वह लगभग पूरी आय परिवार पर खर्च कर रहा था। कुछ मामलों में ऐसा भी हो सकता है। कोई भी दावेदार यह स्वीकार नहीं करेगा कि मृतक खर्चीला था, भले ही वह ऐसा ही क्यों न हो।

दावा याचिका में प्रतिवादियों के लिए यह दिखाने के लिए सबूत पेश करना भी बहुत मुश्किल है कि मृतक अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा खुद पर खर्च कर रहा था या वह अपने परिवार पर आय के केवल एक छोटा सा हिस्सा योगदान दे रहा था। इसलिए, मृतक के व्यक्तिगत और जीवन-यापन के खर्च के तहत की जाने वाली कटौतियों को मानकीकृत करना आवश्यक हो गया। इससे मृतक के व्यक्तिगत और जीवन-यापन के खर्चों के लिए कटौती की प्रथा शुरू हो गई, यदि मृतक विवाहित था तो आय का एक तिहाई, और यदि मृतक कुंवारा था तो आय का आधा (50%)। यह प्रथा अनुभव, तर्क और सुविधा से विकसित हुई थी। वास्तव में मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 163-ए ("संक्षेप में एमवी अधिनियम") के तहत दावों के संबंध में, एक तिहाई कटौती को अधिनियम की दूसरी अनुसूची के तहत

वैधानिक मान्यता मिली है। लेकिन, कटौती का इतना प्रतिशत कोई अनम्य नियम नहीं है और यह केवल एक दिशानिर्देश प्रदान करता है।

15. इसके बाद पीठ ने *केरल राज्य सड़क परिवहन निगम बनाम सुसम्मा थॉमस* (1994) 2 एससीसी 176, *यू.पी.एसआरटीसी बनाम त्रिलोक चंद्रा* (1996)4 एससीसी 362 और *फकीरप्पा बनाम कर्नाटक सीमेंट पाइप फैक्ट्री* (2004) 2 एससीसी 473 के फैसलों का हवाला दिया। अभिनिर्धारित:

"हालांकि कुछ मामलों में व्यक्तिगत और जीवन-यापन के खर्चों के लिए की जाने वाली कटौती की गणना त्रिलोक चंद्र में बताई गई इकाइयों के आधार पर की जाती है, सामान्य प्रथा मानकीकृत कटौती लागू करना है। इस न्यायालय के बाद के कई निर्णयों पर विचार करने के बाद, हमारा विचार है कि जहां मृतक शादीशुदा था, वहां मृतक के व्यक्तिगत और जीवन-यापन के खर्चों के लिए जहां आश्रित परिवार के सदस्यों की संख्या है 2 से 3 है कटौती एक तिहाई (1/3) होनी चाहिए, एक-चौथाई (1/4 वां) जहां आश्रित परिवार के सदस्यों की संख्या 4 से 6 है, और एक-पांचवां (1/5 वां) जहां आश्रित परिवार के सदस्यों की संख्या छह से अधिक है।

16. इस मुद्दे पर हाल ही में *संतोष देवी बनाम नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और अन्य* (सिविल अपील संख्या 3723/2012 जिस पर 23.3.2012 को निर्णय लिया गया) पर विचार किया गया और यह देखा गया:

"न्यायाधिकरण द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण को मंजूरी देना भी संभव नहीं है, जिसे उच्च न्यायालय ने हालांकि बिना कारण बताए दोहराया है कि मृतक ने अपनी कुल कमाई का 1/3 हिस्सा, यानी 500/- रुपये व्यक्तिगत खर्च के लिए खर्च किया होगा। ऐसा लगता है कि न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी और उच्च न्यायालय के

विद्वान एकल न्यायाधीश जीवन की कठिन वास्तविकताओं से पूरी तरह से अनभिज्ञ थे। जिस व्यक्ति की मासिक आय 1,500/- रुपये है, उसके लिए असंभव होगा की वो 1/3 हिस्सा खुद पर खर्च करे और पांच व्यक्तियों वाले परिवार के लिए 2/3 छोड़ें। आम तौर पर, ऐसा व्यक्ति, अधिक से अधिक, अपनी आय का 1/10 वां हिस्सा स्वयं पर खर्च करेगा या उस राशि को व्यक्तिगत खर्च के रूप में उपयोग करेगा और बाकी अपने परिवार के लिए छोड़ देगा।

17. भारत में घरेलू उपभोक्ता व्यय 2006-07 पर राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण रिपोर्ट संख्या-527, जिसे इस विषय पर गहन शोध करने के बाद तैयार किया गया है, विभिन्न वर्गों के लिए मासिक प्रति व्यक्ति व्यय (एमपीसीई) के आंकड़े शामिल हैं। इन्हें नीचे निकाला गया है:

Table 5R: Break-up of total monthly per capita consumer expenditure (MPCE) by groups of items for households in different MPCE classes

All-India														Rural	
item group	monthly per capita expenditure (Rs.) on item group for households in MPCE class (Rs.)													no. of hhs reporting consumption	
	0 - 235	235 - 270	270 - 320	320 - 365	365 - 410	410 - 455	455 - 510	510 - 580	580 - 690	690 - 890	890 - 1155	1155 & more	all classes	per 1000 hhs	sample hhs
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
cereals	67.12	76.36	88.88	95.46	96.64	102.97	107.42	114.03	120.46	125.43	129.52	144.23	114.80	986	32847
gram	0.27	1.04	0.68	0.50	0.68	0.85	0.64	0.88	1.03	1.33	1.73	2.91	1.18	199	7489
cereal substitutes	0.03	0.06	0.03	0.03	0.05	0.12	0.20	0.21	0.41	0.45	0.83	1.94	0.46	71	2837
pulses and their products	5.14	8.11	11.62	13.34	14.45	16.95	18.96	20.54	22.68	27.02	31.42	40.18	22.67	973	32383
milk and milk products	2.86	9.39	8.73	12.07	19.43	27.33	31.27	39.97	52.41	75.89	96.72	151.72	56.23	766	26380
edible oil	7.85	11.47	15.38	16.82	18.93	21.50	23.16	25.36	27.37	32.01	36.68	44.49	27.22	982	32649
egg, fish and meat	3.38	6.31	7.44	10.39	13.29	15.00	17.75	19.79	24.31	29.50	38.74	52.13	24.32	616	23272
vegetables	14.91	20.67	25.39	28.91	30.20	34.50	36.62	40.01	44.79	49.98	56.44	67.88	43.06	986	32826
fruits: fresh	1.11	1.46	2.01	2.82	3.70	4.18	5.19	6.17	8.99	11.75	16.75	32.28	10.02	773	27530
fruits: dry	0.04	0.08	0.30	0.81	0.74	1.04	1.14	1.56	1.87	2.69	4.30	8.82	2.45	298	10146
sugar	3.21	5.06	6.16	7.07	8.10	9.05	10.77	12.04	14.07	17.12	20.61	27.87	14.04	957	31880
salt	0.69	0.79	0.90	1.00	1.00	1.14	1.14	1.21	1.38	1.51	1.77	1.99	1.34	985	32772
spices	5.32	7.50	8.30	9.70	10.77	11.63	12.54	13.90	15.28	17.18	20.19	24.27	14.96	985	32761
beverages, etc.	5.09	7.46	10.29	11.72	14.78	16.27	19.10	22.21	25.79	33.65	46.72	92.60	30.67	982	32800
total: food	**117.01**	**155.76**	**186.10**	**210.63**	**232.76**	**262.53**	**285.92**	**317.88**	**360.84**	**425.50**	**502.44**	**693.32**	**363.42**	**999**	**33123**
pan	0.23	0.41	0.96	1.44	1.87	1.65	1.74	1.99	2.92	3.26	4.67	4.43	2.64	305	10407
tobacco	1.91	3.84	4.80	5.97	5.68	6.05	7.40	8.71	9.02	9.89	11.05	15.17	8,70	618	19528
intoxicants	1.92	2.28	3.58	3.40	4.91	4.11	4.22	4.53	5.90	6.35	7.77	17.63	6.36	181	6278
fuel and light	31.32	36.04	35.25	39.35	43.42	47.66	51.54	58.75	65.74	75.82	90.22	123.85	66.07	995	33093
clothing	15.69	17.42	20.07	23.48	26.64	27.53	32.96	36.54	41.49	49.31	60.54	85.99	42.42	997	33076
footwear	2.26	2.08	2.14	2.71	3.50	3.62	4.36	5.07	5.98	7.97	10.27	15.73	6.53	972	32368

Table 5R (contd.): Break-up of total monthly per capita consumer expenditure (MPCE) by groups of items for households in different MPCE classes

All-India — **Rural**

item group	monthly per capita expenditure (Rs.) on item group for households in MPCE class (Rs.)													no. of hhs reporting consumption	
	0 - 235	235 - 270	270 - 320	320 - 365	365 - 410	410 - 455	455 - 510	510 - 580	580 - 690	690 - 890	890 - 1155	1155 & more	all classes	per 1000 hhs	sample hhs
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
education	1.91	2.14	2.98	5.32	6.07	7.19	8.70	11.03	15.74	24.54	33.70	95.17	22.16	615	21722
medical-institutional	0.25	0.58	0.80	1.57	4.07	4.14	3.67	4.42	5.40	11.31	24.02	94.38	15.55	127	5076
medical-non-inst.	5.26	5.63	9.85	11.75	11.90	17.98	19.29	23.94	28.05	42.80	57.93	125.53	36.74	685	23349
entertainment	0.64	0.69	0.50	0.81	1.71	1.34	2.40	2.34	3.80	4.68	8.76	18.36	4.74	279	11404
goods for personal care	0.23	0.34	0.24	0.29	0.92	0.59	1.08	1.41	1.44	1.99	2.52	4.61	1.63	153	5460
toilet articles	5.42	6.32	7.60	9.41	10.25	11.42	12.79	14.49	16.79	20.18	24.61	43.52	17.87	994	32966
sundry articles	3.98	5.45	5.95	7.14	8.10	9.31	10.38	12.18	14.26	17.12	22.46	31.90	14.65	993	32916
cons. services excluding conveyance	4.31	5.46	7.29	8.20	9.96	11.85	14.33	16.21	21.56	30.51	48.92	109.15	29.09	968	31867
conveyance	2.60	4.07	3.26	4.59	7.16	7.57	10.11	12.04	15.42	26.39	44.51	114.97	25.77	754	27051
rent	0.00	0.00	0.01	0.34	0.23	0.37	0.77	0.65	0.94	2.48	4.31	19.31	3.00	63	2648
taxes and cesses	0.05	0.09	0.22	0.47	0.38	0.58	0.84	0.90	1.16	1.85	2.74	6.46	1.65	347	13380
durable goods total	2.45	6.20	4.59	6.45	6.26	7.44	8.54	11.57	15.76	17.77	40.57	138.13	26.18	844	27399
total: non-food	**80.44**	**99.05**	**110.10**	**132.70**	**153.03**	**170.40**	**195.11**	**226.78**	**271.40**	**354.20**	**499.56**	**1064.28**	**331.75**	**1000**	**33145**
total expenditure	**197.45**	**254.81**	**296.20**	**343.33**	**385.79**	**432.93**	**481.03**	**544.66**	**632.23**	**779.69**	**1002.01**	**1757.60**	**695.16**	**1000**	**33146**
clothing: second hand	0.29	1.12	0.36	0.29	0.39	0.40	0.50	0.26	0.21	0.33	0.27	0.19	0.33	69	2761
footwear: second hand	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.03	0.02	0.02	0.04	0.03	0.02	8	409
2nd hand durable goods	0.05	0.05	0.15	0.00	0.01	0.02	0.02	0.05	0.05	0.34	0.94	5.00	0.65	8	305
estd. no. hhs(00)	19254	27459	57024	72159	107622	118332	146398	170830	242565	259952	186193	200894	1608681		
estd. no. pers(00)	93943	159161	336277	402184	628541	646317	769698	883179	1133508	1197816	799958	733037	7783617		
no. of sample households	228	299	698	1137	1559	1888	2413	3190	4580	6029	4654	6471	33146		
no. of sample persons	1167	1785	4262	6569	9053	10427	13327	16902	23846	29967	21960	25820	165085		

Table 5U: Break-up of total monthly per capita consumer expenditure (MPCE) by groups of items for households in different MPCE classes

All-India — Urban

	monthly per capita expenditure (Rs.) on item group for households in MPCE class (Rs.)													no. of hhs reporting consumption	
	0 – 335	335 – 395	395 – 485	485 – 580	580 – 675	675 – 790	790 – 930	930 - 1100	1100 - 1380	1380- 1880	1880- 2540	2540 & more	all classes	per 1000 hhs	sample hhs
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
cereals	72.87	85.96	90.75	99.71	105.84	107.86	114.19	117.79	124.64	131.56	142.38	151.16	118.80	948	29024
gram	0.42	0.47	0.56	0.74	0.94	1.02	1.40	1.73	2.02	2.44	2.55	3.00	1.68	271	8232
cereal substitutes	0.06	0.09	0.20	0.34	0.26	0.44	0.44	0.46	0.52	0.60	0.75	1.02	0.50	88	2256
pulses and their products	12.12	15.17	17.13	20.62	22.74	25.13	27.37	29.24	32.13	36.60	40.93	47.25	30.06	938	28697
milk and milk products	11.25	20.39	25.29	33.76	46.68	57.50	69.83	89.31	107.14	138.01	161.88	235.62	97.49	893	27409
edible oil	14.12	18.39	20.81	23.42	27.76	30.42	33.38	36.21	42.06	46.33	52.12	59.81	37.52	941	28810
egg, fish and meat	6.93	10.97	15.13	19.44	24.33	25.20	29.93	30.71	37.40	41.02	51.46	67.53	34.20	571	17945
vegetables	20.84	27.36	30.75	37.88	39.80	43.50	50.49	54.18	62.46	70.31	77.18	98.71	56.87	943	28884
fruits: fresh	2.63	3.59	4.62	7.01	8.63	10.16	13.03	15.39	21.44	29.66	40.18	71.11	21.97	887	27616
fruits: dry	0.44	0.87	1.31	1.35	1.73	2.54	2.78	3.62	4.81	7.18	13.28	23.46	6.03	419	13278
sugar	7.14	8.67	10.65	11.01	13.41	14.71	16.05	17.94	19.17	20.20	22.76	25.53	17.25	933	28576
salt	0.88	0.96	1.10	1.21	1.37	1.47	1.57	1.68	1.82	1.88	2.03	2.35	1.66	942	28847
spices	7.70	10.20	12.02	13.98	14.97	16.37	17.37	19.08	20.40	21.50	23.75	28.40	18.82	941	28825
beverages, etc.	13.00	16.89	18.39	25.11	29.26	35.05	41.58	50.99	66.57	91.22	126.27	271.33	74.42	997	30485
total: food	**170.42**	**219.98**	**248.70**	**295.59**	**337.73**	**371.37**	**419.42**	**468.31**	**542.58**	**638.49**	**757.51**	**1086.28**	**517.25**	**999**	**30562**
pan	0.72	1.30	1.88	2.66	2.21	2.62	2.78	3.02	3.82	3.66	4.41	4.09	3.12	199	7097
tobacco	3.81	4.36	5.90	8.08	6.78	8.22	8.81	9.26	8.85	10.00	9.92	17.03	9.22	356	10914
intoxicants	1.50	1.69	3.44	4.38	5.16	4.28	5.40	4.49	6.31	7.21	6.73	16.04	6.24	99	3164
fuel and light	38.42	47.01	56.77	64.68	73.68	85.05	92.24	107.32	123.75	143.54	171.36	255.81	117.44	993	30384
clothing	19.05	22.96	28.70	31.85	37.90	43.39	49.12	59.90	67.98	85.86	114.21	188.80	70.25	997	30498
footwear	2.59	3.12	4.21	4.67	5.95	7.22	8.53	10.36	12.49	16.94	23.06	38.19	13.07	985	30137

All India — **Urban**

item group	monthly per capita expenditure (Rs.) on item group for households in MPCE class (Rs.)													no. of hhs reporting consumption	
	0 - 335	335 - 395	395 - 485	485 - 580	580 - 675	675 - 790	790 - 930	930 - 1100	1100 - 1380	1380 - 1880	1880 - 2540	2540 & more	all classes	per 1000 hhs	Sample hhs
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
education	5.27	6.35	11.39	13.21	21.68	26.58	38.02	48.73	68.44	110.25	182.02	424.68	91.60	721	22518
medical-institutional	2.34	1.10	2.43	6.17	3.94	8.64	10.39	12.16	16.90	24.35	40.18	128.41	24.35	140	4199
medical-non-inst.	8.69	12.90	18.23	24.15	25.34	34.30	44.93	46.19	55.71	73.29	95.96	167.96	58.23	718	21973
entertainment	0.77	1.60	2.91	4.97	7.14	9.09	12.55	16.06	22.37	32.77	48.10	87.27	24.05	581	19683
goods for personal care	0.22	0.37	0.51	0.59	0.67	1.15	1.41	2.36	2.08	3.30	6.58	10.97	2.88	133	5258
toilet articles	8.77	10.66	12.76	15.53	18.44	21.17	24.14	27.43	32.82	41.09	52.05	72.65	31.82	998	30516
sundry articles	6.18	8.35	9.75	12.27	14.40	16.87	19.41	21.50	26.65	33.32	43.24	63.92	26.09	992	30388
cons. services excluding conveyance	7.04	9.85	13.50	15.78	21.54	29.19	38.73	54.04	75.79	118.46	201.07	447.68	98.57	979	29926
conveyance	4.61	4.88	7.09	10.77	18.12	23.05	29.58	45.66	67.06	103.32	162.52	369.38	81.63	842	26258
rent	3.25	5.98	7.08	12.33	14.33	24.18	32.43	46.06	59.31	91.58	125.05	264.55	66.96	365	10449
taxes and cesses	0.65	1.56	1.96	2.31	3.41	5.00	5.68	7.42	8.76	11.72	18.93	42.49	10.52	521	16087
durable goods total	2.59	3.85	5.71	7.37	9.53	12.40	15.83	20.77	28.46	51.14	96.82	382.12	59.21	818	24981
total: non-food	**116.48**	**147.88**	**194.23**	**241.77**	**290.24**	**362.40**	**439.97**	**542.72**	**687.55**	**961.82**	**1402.21**	**2982.06**	**795.25**	**1000**	**30583**
total expenditure	**286.90**	**367.85**	**442.94**	**537.36**	**627.96**	**733.77**	**859.40**	**1011.04**	**1230.14**	**1600.31**	**2159.72**	**4068.34**	**1312.50**	**1000**	**30583**
clothing: second hand	**0.82**	**0.53**	**0.39**	**0.31**	**0.32**	**0.34**	**0.30**	**0.22**	**0.17**	**0.17**	**0.16**	**0.09**	**0.25**	**38**	**1587**
footwear: second hand	**0.02**	**0.05**	**0.03**	**0.02**	**0.03**	**0.01**	**0.03**	**0.01**	**0.03**	**0.03**	**0.01**	**0.03**	**0.02**	**9**	**276**
2nd hand durable goods	**0.00**	**0.08**	**0.04**	**0.08**	**0.20**	**0.32**	**0.23**	**0.21**	**0.50**	**1.08**	**0.87**	**6.14**	**0.92**	**11**	**304**
imputed rent	**50.98**	**60.83**	**73.44**	**91.30**	**107.16**	**123.44**	**143.57**	**170.39**	**211.24**	**284.56**	**472.82**	**826.60**	**245.22**	**653**	**20248**
estd. no. hhs(00)	**6764**	**9524**	**23316**	**37046**	**38559**	**46300**	**58647**	**62420**	**78203**	**82775**	**58892**	**75987**	**578434**		
estd. no. pers(00)	36334	59014	138395	195388	207808	228906	275815	275004	324424	312892	209981	219963	2483925		
no. of sample households	265	335	837	1259	1423	1795	2269	2561	3939	5885	4739	5276	30583		
no. of sample persons	1539	2101	4983	6902	7623	9220	11009	11810	17022	23096	16372	15151	126828		

18. यहां, हम एक ऐसे मामले से निपट रहे हैं जिसमें मृतक के चार बेटे और एक बेटी सहित 8 आश्रित थे। हमारे विचार के लिए यह प्रश्न उठता है कि क्या 1992 में एक व्यक्ति जिसकी आय 3000/- रुपये से कम थी और उसका परिवार 9 लोगों का था, क्या वह अपनी आय का 1/3 हिस्सा स्वयं पर खर्च करने के बारे में सोच सकता था? एक रूढ़िवादी अनुमान के आधार पर, यह कहना संभव है कि उसने अपनी आय का कम से कम 50% अनाज, दूध, आदि की खरीद और पानी, बिजली और अन्य बिलों के भुगतान पर खर्च किया होगा। आय का 25% बच्चों की शिक्षा पर खर्च किया होगा जिसमें स्कूल/कॉलेज की फीस, किताबों की लागत आदि शामिल होगी। आय का 15% अन्य पारिवारिक आवश्यकताओं, जैसे कपड़े, चिकित्सा व्यय, आदि को पूरा करने के लिए उपयोग किया होगा। तब उसके पास अपनी आय का 10% हिस्सा बचता था, जिसका एक हिस्सा अप्रत्याशित आकस्मिकताओं को पूरा करने और त्योहारों के अवसर पर इस्तेमाल किया जा सकता था। इस परिदृश्य में, व्यक्तिगत खर्चों के लिए कोई भी कटौती अवास्तविक होगी। किसी भी मामले में, जहां मृतक के परिवार में 5 व्यक्ति या अधिक शामिल हैं और उनकी आय 3,000/- रुपये से 5,000/- रुपये है, तो उसके लिए कुल आय का 1/10 से अधिक खर्च करना लगभग असंभव है।

19. हमने ऊपर जो देखा है वह शहरी क्षेत्रों में रहने वाले अमीर लोगों पर लागू नहीं हो सकता है जो क्लबों, होटलों और पेय पार्टियों में अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा खर्च कर सकते हैं। उन मामलों में, 1/3 कटौती के नियम को लागू करने में औचित्य की झलक हो सकती है लेकिन उस नियम को सभी मामलों में सार्वभौमिक रूप से लागू करना पूरी तरह से अवास्तविक होगा।

20. उपरोक्त चर्चा के आधार पर, हम मानते हैं कि उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने मृतक के व्यक्तिगत खर्चों के लिए 1/3 कटौती के नियम का पालन न करके कोई त्रुटि नहीं की।

21. हमारा यह भी मानना है कि उच्च न्यायालय द्वारा मृतक की आय में 100% वृद्धि की अनुमति देकर मुआवजे की राशि निर्धारित करना उचित था। सामान्य स्थिति में, मृतक ने 22 वर्षों तक सेवा की होती और उस अवधि के दौरान उसका वेतन निश्चित रूप से दोगुना हो गया होता क्योंकि नियोक्ता प्रति वर्ष बोनस के रूप में उसके वेतन का 20% भुगतान कर रहा था।

22. जिस मुद्दे पर विचार किया जाना बाकी है वह यह है कि क्या न्यायाधिकरण और उच्च न्यायालय ने गुणक लागू करके कोई त्रुटि की है।

23. *सरला वर्मा बनाम दिल्ली परिवहन निगम* (उपर्युक्त) में, इस न्यायालय ने गुणक के चयन से संबंधित प्रश्न पर विचार किया, *केरल राज्य सड़क परिवहन निगम बनाम सुसम्मा थॉमस* (उपर्युक्त), यूपीएसआरटीसी बनाम त्रिलोक चंद्र (उपर्युक्त) के निर्णयों और अधिनियम से जुड़ी दूसरी अनुसूची का हवाला दिया, और कहा:

> "इसलिए हमारा मानना है कि उपयोग किए जाने वाले गुणक को उपरोक्त तालिका के कॉलम (4) में जैसा उल्लिखित है, होना चाहिए (सुसम्मा थॉमस, त्रिलोक चंद्र और चार्ली को लागू करके तैयार किया गया है), जो 18 के ऑपरेटिव गुणक से शुरू होता है (15 से 20 और 21 से 25 साल के आयु समूहों के लिए), हर पांच साल में एक यूनिट कम हो जाती है, यानी 26 से 30 साल के लिए एम-17, 31 से 35 साल के लिए एम-16, 36 से 40 साल के लिए एम-15, 41 से 45 वर्ष के लिए एम-14, और 46 से 50 साल के लिए एम-13, फिर

हर पांच साल के लिए दो यूनिट कम कर दी जाती है, यानी 51 से 55 साल के लिए एम-11, 56 से 60 साल के लिए एम-9, 61 से 65 साल के लिए एम-7 और एम-5 66 से 70 वर्ष तक।"

24. इसमें कोई विवाद नहीं है कि दुर्घटना के समय मृतक की उम्र 36 वर्ष थी। इसलिए, न्यायाधिकरण और उच्च न्यायालय 10 के गुणक को लागू करने में सही नहीं थे। उन्हें मुआवजे की राशि निर्धारित करने के उद्देश्य से 15 के गुणक को अपनाना चाहिए था।

25. परिणामस्वरूप, अपील खारिज की जाती है। हालाँकि, दावेदारों के साथ पूर्ण न्याय करने की दृष्टि से, हम स्वत: संज्ञान लेते हुए 15 के गुणक को लागू करके निम्नलिखित शर्तों में मुआवजे की राशि को फिर से निर्धारित करते हैं और मानते हैं कि दावेदार कुल 10,63,040 रुपये की राशि के हकदार हैं। /-:

मुआवजे की रकम, 12 महीने के वेतन और 15 गुणक के साथ: रु. 5378 x 12 x 15 = 9,68,040 रुपये

[रु.2,689 प्रति माह x 2= रु. 5,378/- पीएम]

प्यार और स्नेह की हानि, सुरक्षा के अभाव, सामाजिक सुरक्षा, आदि के लिए परिवार के सदस्यों को मुआवजा : रु. 70,000/-

प्यार और स्नेह की हानि, दर्द और पीड़ा, सह-व्यवस्था की हानि, सुरक्षा की कमी, सामाजिक सुरक्षा की कमी आदि के लिए मृतक की विधवा को मुआवजा: रु. 25,000/-

कुल मुआवज़ा: रु.10,63,040 [रु.9,68,040 + रु.70,000 + रु. 25,000]

26. दावेदारों को दावा याचिका दायर करने की तारीख से 12% प्रति वर्ष की दर से बढ़े हुए मुआवजे पर ब्याज भी मिलेगा।

27. अपीलकर्ता को छह सप्ताह की अवधि के भीतर प्रतिवादी नंबर 2, यानी मृतक की विधवा के नाम पर एक डिमांड ड्राफ्ट तैयार करके दावेदारों को बढ़ा हुआ/अतिरिक्त मुआवजा और ब्याज का भुगतान करने का निर्देश दिया जाता है। मुआवजा प्राप्त करने वालों को 50% राशि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में तीन साल की अवधि की सावधि जमा में निवेश करनी होगी।

28. चूंकि अपीलकर्ता ने पांच साल की अवधि के लिए इस न्यायालय द्वारा पारित एकपक्षीय अंतरिम आदेश का लाभ लिया था, इसलिए उसे दावेदारों को 5 लाख रुपये की लागत का भुगतान करने का निर्देश दिया गया है।

29. अपीलकर्ता को राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ की रजिस्ट्री में अनुपालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करना होगा। रजिस्ट्री रिपोर्ट के अवलोकन के लिए मामले को उचित पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करेगी। यदि खंडपीठ को पता चलता है कि अपीलकर्ता इस आदेश में निहित निर्देशों का पालन करने में विफल रहा है, तो वह अपीलकर्ता के अधिकारियों के खिलाफ अदालत की अवमानना अधिनियम, 1971 के तहत कार्यवाही शुरू करेगी और भूमि राजस्व के बकाया के रूप में राशि की वसूली का भी आदेश देगी।

आर.पी.

अपील खारिज।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक अशोक कुमार मीना द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।